



मोहाली एयरपोर्ट के लिए नया शॉर्ट रूट, हरियाणा सरकार उठाएगी पूरा खर्च



चंडीगढ़, 23 मई 2026:मोहाली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंच को आसान बनाने के लिए प्रस्तावित नए शॉर्ट रूट परियोजना पर काम तेज हो गया है। हरियाणा सरकार ने इस परियोजना का पूरा खर्च उठाने की पेशकश की है, जिससे पंचकूला, चंडीगढ़ और ट्राइसिटी के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अधिक खपत होती है।

नया मार्ग बनने के बाद एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी तथा ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना क्षेत्र के विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार भूमि अधिग्रहण और तकनीकी सर्वे सहित अन्य प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्राइसिटी क्षेत्र में व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

हिमाचल में तेज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी



शिमला, 23 मई 2026:मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।

मौसम में अचानक बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग ने किसानों को भी फसलों और बागवानी को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

विकसित भारत के लिए समावेशी AI पर मंथन, ISB-मोहाली में जुटे नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ



मोहाली, 23 मई 2026:भारतीय स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से ISB के मोहाली परिसर में “गवर्नेंस समिट 2026: विकसित भारत के लिए समावेशी AI” का आयोजन किया। इस एक दिवसीय शिखर सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के समावेशी और जिम्मेदार उपयोग पर विचार-विमर्श किया।

समिट के चौथे संस्करण का उद्घाटन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन, IAS ने किया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा AI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की

दिशा में कार्य कर रहा है, जो समाज के हर वर्ग, विशेषकर डिजिटल रूप से वंचित लोगों तक लाभ पहुंचा सके। उन्होंने AI को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन, विनिर्माण और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाली तकनीक बताते हुए कहा कि भारत के पास इसे समावेशी विकास के साधन के रूप में अपनाने का बड़ा अवसर है।

श्री कृष्णन ने यह भी कहा कि भारत को ऐसे AI मॉडल विकसित करने होंगे, जो देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करें तथा तकनीकी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करें। उन्होंने AI के कारण रोजगार और संज्ञानात्मक कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उठ रही चिंताओं का भी उल्लेख किया।

ISB के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्विनी छत्रे ने कहा कि AI को केवल तकनीक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने असमानता, रोजगार के भविष्य और तकनीकी अवसरों को AI विमर्श के महत्वपूर्ण पहलू बताया। वहीं, संस्थान की निदेशक डॉ. आरुषि जैन ने कहा कि सही सार्वजनिक नीतियां ही AI को बहिष्कार नहीं बल्कि समावेशन का माध्यम बना सकती हैं।

दिनभर चले कार्यक्रम में डिजिटल वाणिज्य, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, रोजगार सृजन और डिजिटल उद्यमिता जैसे विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। साथ ही, ग्रामीण स्तर तक सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम-मील डिलीवरी में AI की भूमिका पर विशेष गोलमेज चर्चा भी

सीटीयू से निकाले कर्मचारियों की बहाली की मांग तेज, भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी

चंडीगढ़, 23 मई:भारतीय मजदूर संघ, चंडीगढ़ ने यूटी प्रशासन, नगर निगम और विभिन्न विभागों में कार्यरत कांटेक्ट एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संघ की मुख्य कार्यकारी बैठक में सीटीयू से निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तुरंत वापस रखने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह मुद्दा पहले भी जनता दरबार में चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सीटीयू से निकाले गए कर्मचारी नई बसों के इंतजार में लंबे समय से घर बैठे हैं, जिससे उनके परिवार आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

भारतीय मजदूर संघ ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़



प्रशासन और नगर निगम में वर्षों से सेवा दे रहे हजारों कांटेक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारी आज भी असुरक्षा के माहौल में काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर स्थायी नीति न होने के कारण कर्मचारियों में भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है।

संघ ने मांग की कि लंबे समय से सेवा दे रहे कांटेक्ट कर्मचारियों को एकमुश्त नीति बनाकर नियमित किया जाए। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निजी ठेकेदारों और जेम पोर्टल व्यवस्था से हटाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी केंद्रीकृत सरकारी व्यवस्था के तहत लाया जाए, ताकि भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संघ ने कर्मचारियों के लिए समान कार्य पर सम्मानजनक वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करने की भी मांग की। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगा।

ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हिमाचल हाईकोर्ट की बड़ी पहल



शिमला, 23 मई 2026:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बढ़ती ईंधन खपत, ट्रैफिक दबाव और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार-पूलिंग तथा वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य ईंधन की बचत करना, वाहनों की संख्या कम करना और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को घटाना है।

हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार कार्यालय आने-जाने के दौरान बड़ी संख्या में निजी वाहनों के उपयोग से ईंधन की खपत बढ़ रही थी और ट्रैफिक की समस्या भी गंभीर होती जा रही थी। इसी को देखते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को एक ही वाहन में सामूहिक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके साथ ही कुछ विभागों और कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा भी दी जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पहले से ही पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे में यह पहल अन्य सरकारी संस्थानों और विभागों के लिए भी उदाहरण बन सकती है।

हाईकोर्ट के इस फैसले को आधुनिक कार्य संस्कृति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल कार्यप्रणाली और ऑनलाइन सुनवाई जैसी व्यवस्थाओं के बढ़ते उपयोग के बीच वर्क-फ्रॉम-होम मॉडल कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों की बचत में भी सहायक हो सकता है।

इस पहल से कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करने और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिल सकेगा। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को लेकर हाईकोर्ट की यह पहल राज्य में जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगी।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।

TruSoft

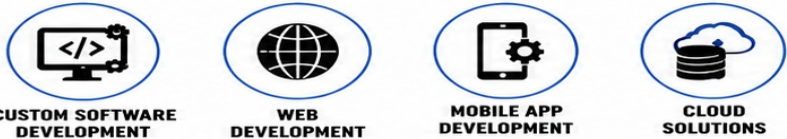
GST ACCOUNTING SOFTWARE WITH INVENTORY CONTROLS

ERP

Software that touches every part of your business.

SOFTWARE & WEB DEVELOPMENT

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”



ALSO FOR:

➔ Clinical Labs
➔ Schools
➔ Drycleaners
➔ Transportation

➔ Pharmaceuticals
➔ Library
➔ Non Banking/Finance
➔ Weighing Scales

➔ Institutes
➔ Readymade Garments
➔ Dairies
➔ Cold Storage

➔ Hotels, Restaurants
➔ Apparels, Footwear
➔ Shuttering
➔ Sabzi Mandi



- ACCURATE ACCOUNTING
- INVENTORY CONTROLS
- GST COMPLIANCE
- SIMPLE & SECURE
- RELIABLE SUPPORT

CALL US TODAY!

+91-9041012531



herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY